प्रेस विज्ञप्ति

इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने विश्व आर्थिक मंच में भारत के सौर नेतृत्व पर प्रकाश डाला



दावोस, 21 जनवरी 2026

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने आज विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू.ई.एफ.) दावोस 2026 में "स्केलिंग सोलर वेयर इट मैटर्स: ग्लोबल साउथ के लिए रूफटॉप, एग्रीकल्चर और डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी पर भारत की सीख" विषय पर एक पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। इससे पहले, माननीय केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने मुख्य भाषण दिया।

इस सेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर में भारत की ग्लोबल लीडरशिप और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसकी बढ़ती प्रासंगिकता पर ज़ोर दिया गया। उन्होंने कहा कि डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने से सिस्टम में एफिशिएंसी बढ़ सकती है, जिससे सरकारी सब्सिडी और एटी एंड सी नुकसान कम होंगे, जिससे लागत में काफी कमी आएगी और यह किफायती भी होगा।

नए और उभरते रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट से जुड़े जोखिमों पर चर्चा के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए, श्री दास ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हालांकि उभरते रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट को अक्सर रिस्क प्रोफाइलिंग के मामले में चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन प्रभावी प्रोजेक्ट डिज़ाइन और समझदारी भरा रिस्क मैनेजमेंट इन क्षेत्रों में जोखिम को काफी कम कर सकता है। यह इरेडा के 38 से ज़्यादा सालों के परिचालन में सिर्फ़ ₹149 करोड़ के बहुत कम कुल राइट-ऑफ से साफ़ है, जबकि शुरुआत से अब तक लगभग ₹1.81 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग की गई है, जो कंपनी के मज़बूत मूल्यांकन और मॉनिटरिंग सिस्टम को दिखाता है।

उन्होंने बताया कि इरेडा रूफटॉप सोलर और पीएम-कुसुम योजनाओं के तहत एग्रीगेटर मोड में प्रोजेक्ट लागत का 70-80% फाइनेंस करता है, जिससे पूरे ग्रामीण भारत में स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में काफी तेज़ी आई है।





श्री दास ने माननीय केंद्रीय मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी को, विश्व आर्थिक मंच पर इरेडा को मंच प्रदान करने हेतु धन्यवाद ज्ञपित किया। जिससे न केवल एक प्रौढ़ तंत्र के द्वारा भारत की अक्षय ऊर्जा की विकास यात्रा को प्रदर्शित किया जा रहा है, बल्कि देश में इस बदलाव को आगे बढ़ाने में इरेडा की अहम भूमिका को भी रेखांकित किया जा रहा है। जो दूसरों के लिए उनकी अक्षय ऊर्जा की यात्रा में एक मूल्यवान सीख साबित हो सकती है। महाराष्ट्र में कृषि सौर ऊर्जाकरण में हुई प्रगति का उदाहरण देते हुए। उन्होंने एक ऐसे तंत्र निर्माण की आवश्यकता ज़ोर दिया जो इस क्षेत्र के जोखिम को कम करे और वैश्विक पूंजी को आकर्षित करें।